Toppersnotes®
Unleash the topper in you

HPSC

हरियाणा लोक सेवा आयोग

Haryana Public Service Commission

सामान्य अध्ययन

पेपर – 3 भाग – 1 (द)

सामाजिक प्रासंगिकता

SIERRA INNOVATIONS

Haryana Public Service Commission

पेपर - 3 भाग - 1 (द) - सामाजिक प्रासंगिकता

S.No.	Chapter Name	Page No.
	सामाजिक न्याय	
1.	**विकास** • मानव विकास के उद्देश्य • मानव विकास के घटक	1
2.	**अल्पसंख्यक** • अल्पसंख्यक समूह के प्रकार • भारत में अल्पसंख्यक ○ संवैधानिक प्रावधान ○ भारत में अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली समस्याएं ○ अल्पसंख्यकों के प्रति आक्रोश का कारण • अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा और रोजगार • सरकार की पहल	4
3.	**आरक्षण** • ऐतिहासिक विकास • आरक्षण की आवश्यकता • संवैधानिक प्रावधान • प्रमोशन में आरक्षण की मांग • आरक्षण प्रणाली की चिंताएं/चुनौतियां	6
4.	**शहरीकरण** • भारतीय शहरीकरण की विशेषताएं • शहरीकरण की प्रक्रिया • भारत में शहरीकरण का विकास • शहरीकरण के कारण • शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव • शहरीकरण के वर्तमान मॉडल • शहरीकरण के मुद्दे • शहरीकरण के उपाय • नव गतिविधि	10
5.	**वैश्वीकरण** • वैश्वीकरण की सहायता करने वाले कारक • वैश्वीकरण के प्रभाव • वैश्वीकरण 4.0	16
6.	**कमजोर वर्ग** • कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का औचित्य • समाज के कमजोर वर्ग • बाल ○ बच्चों से जुड़े मुद्दे ○ यौन शोषण ○ बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कानून	20

	○ बाल श्रम ○ बाल विवाह • अनुसूचित जनजाति/SC/OBC ○ अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाएं ○ अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं ○ ओबीसी के लिए योजनाएं • युवा • वरिष्ठ नागरिक • विकलांग व्यक्ति • अल्पसंख्यकों • LGBT समुदाय	
7.	**शिक्षा** • भारत में शिक्षा • भारत में शिक्षा की स्थिति • संवैधानिक प्रावधान • शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 • राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 • भारत में शिक्षा ○ सरकार की पहल ○ माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा ○ उच्च शिक्षा	**32**
8.	**गरीबी** • गरीबी के आयाम • गरीबी के प्रकार • भारत में गरीबी के कारण • भारत में गरीबी का अनुमान • गरीबी पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें • रंगराजन समिति	**39**
9.	**जनसंख्या और संबंधित मुद्दे** • जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस का सिद्धांत • जनसांख्यिकीय संक्रमण • जनसंख्या पिरामिड • भारतीय जनसंख्या के निर्धारक • जनसांख्यिकीय विभाजन • जनसंख्या नियंत्रण • परिवार नियोजन • जनसंख्या के मुद्दे • प्रवासन • बेघर • राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 • संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)	**45**
10.	**स्वास्थ्य** • संवैधानिक प्रावधान • स्वास्थ्य संकेतक • भूख और कुपोषण	**54**

	• वैश्विक भूख सूचकांक • भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और बुनियादी ढांचा • यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज • स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में PPP मॉडल • नीतिगत ढांचा ○ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) (2013) ○ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ○ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 ○ आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) ○ राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, 2020 • आयुष	
11.	**महिला एवं महिला संगठन** • भारत में महिलाएं • वर्तमान स्थिति • राजनीतिक स्थिति • आर्थिक स्थिति • सामाजिक स्थिति • सांस्कृतिक स्थिति • विविध मुद्दे	**65**
	आंतरिक सुरक्षा	
1.	**सुरक्षा** • राष्ट्रीय सुरक्षा • खतरों के प्रकार • सुरक्षा के लिए वैश्विक चुनौतियां • गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दे ○ खाद्य सुरक्षा ○ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण ○ पानी की कमी और प्रदूषण ○ ऊर्जा सुरक्षा मुद्दे ○ सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे ○ आपदाएं ○ अवैध प्रवास ○ मानव सुरक्षा के मुद्दे ○ गरीबी ○ परमाणु सुरक्षा मुद्दे ○ रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रसार: ○ आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे • बाह्य राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका • आंतरिक सुरक्षा	**73**
2.	**भारतीय सीमाएँ और उनका प्रबंधन** • सीमा प्रबंधन • सीमा अवसंरचना • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को पुलिसिंग शक्ति • भारत की प्रमुख सीमाएँ ○ भारत-पाकिस्तान सीमा	**81**

	○ भारत-चीन सीमा ○ भारत-नेपाल सीमा ○ भारत-बांग्लादेश सीमा ○ भारत-म्यांमार सीमा ○ भारत-भूटान सीमा	
3.	**तटीय और समुद्री सुरक्षा** • तटीय सुरक्षा • मौजूदा संरचना में मुद्दे • मौजूदा संरचना में अंतराल को भरने के तरीके • समुद्री सुरक्षा • खुफिया एजेंसियां • अनुसंधान और विकास संगठन • तटीय सुरक्षा संरचना • इलेक्ट्रॉनिक निगरानी • समुद्री सुरक्षा के लिए सरकार की पहल	**93**
4.	**आतंकवाद** • आतंकवाद के साधन • आतंकवाद का वर्गीकरण • आतंकवाद के प्रकार • आतंकवाद के कारण • भारत में आतंकवाद ○ पाकिस्तान की राज्य नीति के रूप में आतंक ○ भारत में आतंकवाद की श्रेणियाँ ○ 'हॉट परस्यूट' और 'सर्जिकल स्ट्राइक' ○ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की रणनीति ○ भारत के आतंकवाद विरोधी उपाय • आतंकवाद के लिए वित्तपोषण • आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के कदम • आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार की पहल	**98**
5.	**वामपंथी उग्रवाद** • नक्सलबाड़ी घटना • वामपंथी उग्रवाद का विकास • लक्ष्य • नक्सली आंदोलनों का फोकस • नक्सलवाद का आतंकी संगठनों से जुड़ाव • वर्तमान स्थिति • नक्सली आंदोलन की रणनीति • नक्सलियों का राजनीतिक संगठन • फ्रंट संगठन और शहरी उपस्थिति • वामपंथी उग्रवाद के कारण • वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव • सरकारी पहल • वामपंथी उग्रवाद से निपटने में समस्याएं • पूर्वी भारत में उग्रवाद के कारण • उत्तर पूर्व भारत में उग्रवाद के कारण	**107**

	• दक्षिण भारत में उग्रवाद के कारण • उग्रवाद से निपटने के उपाय	
6.	**उत्तर पूर्व में उग्रवाद** • संघर्षों की श्रेणियाँ • उग्रवाद का मूल कारण • उत्तर पूर्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि • उत्तर पूर्व में शांति बनाए रखने का महत्व • चरमपंथ के मामले में पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति ○ नौ सूत्री समझौता (1947) ○ सोलह सूत्री समझौता (1960) ○ शिलांग समझौता (1975) ○ नागा शांति समझौता 2015 • पूर्वोत्तर में प्रमुख उग्रवादी समूह • सरकारी पहलें • संवैधानिक प्रावधान • पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम/योजनाएं	**114**
7.	**जम्मू-कश्मीर में विद्रोह** • इतिहास • छद्म युद्ध और कश्मीर • कश्मीर और मानवाधिकार • कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में बदलाव • सरकारी पहलें • कश्मीर की वर्तमान स्थिति	**125**
8.	**संगठित अपराध** • संगठित अपराधों के प्रकार • भारतीय राज्यों में संगठित अपराध की पैठ • सरकारी पहल • नियंत्रण उपायों को अपनाने में समस्याएं	**127**
9.	**कट्टरतावाद** • कट्टरतावाद के पीछे कारक • कट्टरतावाद के रूप • कट्टरतावाद से निपटने के लिए कदम • हालिया विकास • डिजिटल कट्टरतावाद	**131**
10.	**सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा** • समस्या की प्रकृति • संवैधानिक और कानूनी प्रावधान • सांप्रदायिक हिंसा पैदा करने वाले कारक • शासन के मुद्दे • सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के उपाय • भारत में सांप्रदायिक हिंसा की प्रमुख घटनाएं ○ भारत का विभाजन, 1947 ○ 1984 के सिख-विरोधी दंगे ○ 1989 में कश्मीरी हिंदू पंडितों की जातीय सफाई/ का नरसंहार ○ अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस, 1992 ○ असम सांप्रदायिक हिंसा, 2012 ○ मुजफ्फरनगर हिंसा, 2013	**133**

	○ नई दिल्ली दंगे, 2020 • सांप्रदायिक हिंसा का प्रभाव • सरकारी पहलें	
11.	**भारत में क्षेत्रवाद** • भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों का इतिहास • क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रकार • क्षेत्रवाद के विकास के पीछे कारण • क्षेत्रवाद का प्रभाव • क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रवाद • क्षेत्रवाद से निपटने के सुझाव	**138**
12.	**साइबर सुरक्षा** • साइबरस्पेस का महत्व • भारत में साइबर सुरक्षा • साइबर हमलों के पीछे की मंशा • साइबर हमलों के प्रकार • साइबर सुरक्षा के घटक • साइबर सुरक्षा की आवश्यकता • अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना (सीआईआई) • साइबर आतंकवाद • आतंकवादी द्वारा साइबर स्पेस का उपयोग • भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकारी पहल • साइबर सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल • भारत में साइबर सुरक्षा के लिए चुनौतियां • डेटा सुरक्षा • 5जी और साइबर सुरक्षा • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा	**141**
13.	**आंतरिक सुरक्षा में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स** • भारत में मीडिया की भूमिका • सोशल मीडिया की विशेषताएं • सोशल मीडिया के आयाम • राष्ट्रीय सुरक्षा पर सोशल मीडिया के प्रभाव • आंतरिक सुरक्षा को सोशल मीडिया से खतरा • मीडिया/सोशल मीडिया के कारण हालिया आंतरिक सुरक्षा संकट • सरकारी पहलें • सोशल मीडिया के नियमन की आवश्यकता • सोशल मीडिया के नियमन के मुद्दे • पुलिसिंग में सोशल मीडिया का प्रयोग	**149**
14.	**धन शोधन** • प्रक्रिया • मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक • मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव • सरकारी पहलें • वैश्विक पहल	**153**
15.	**पुलिस सुधार** • संगठनात्मक संरचना • पुलिस का विकास	**156**

	• पुलिस के कार्य • पुलिस के संबंध में केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी • पुलिस द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं • मौजूदा पुलिस कार्यप्रणाली में मुद्दे • पुलिस सुधार • स्मार्ट पुलिसिंग	
पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता		
1.	**पर्यावरण** • पर्यावरण क्षरण • पर्यावरणवाद • भारत में प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन • पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास • पर्यावरण के लिए भारतीय प्रयास • वैश्विक और भारतीय पर्यावरण कोष	**159**
2.	**प्रदूषण** • प्रदूषक • वायु प्रदूषण ○ प्रमुख वायु प्रदूषक एवं उनके स्रोत ○ घर के अंदर का वायु प्रदूषण ○ वायु प्रदूषण के प्रभाव: ○ वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय: ○ वायु प्रदूषण को कम करने की वैश्विक पहल ○ वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारतीय पहल • जल प्रदूषण ○ जल प्रदूषण / प्रदूषक के स्रोत ○ जल प्रदूषण का मापन ○ जल प्रदूषण के प्रभाव ○ नदी प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार के प्रयास: ○ जल प्रदूषण को रोकने के लिए वैश्विक पहल ○ यूट्रोफिकेशन ○ अम्ल वर्षा • मृदा प्रदूषण ○ मृदा प्रदूषण के स्रोत ○ मृदा प्रदूषण के प्रभाव ○ उपचारात्मक उपाय ○ मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक उपाय ○ मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय पहल • ध्वनि प्रदूषण ○ ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव ○ ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण ○ केंद्र सरकार का विनियमन • रेडियोधर्मी प्रदूषण	**168**

	○ विकिरणों के प्रकार और उनके प्रभाव ○ विकिरण के स्रोत ○ विकिरण कणों के प्रकार ○ नियंत्रण उपाय • ऊष्मीय प्रदूषण ऊष्मीय प्रदूषण के स्रोत ○ थर्मल प्रदूषण का प्रभाव ○ ऊष्मीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय • पारा प्रदूषण ○ पर्यावरण में पारा का स्रोत ○ भारत में पारा संदूषण ○ पारा प्रदूषण के प्रभाव ○ मीनामाता रोग	
3.	**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** • अपशिष्ट का वर्गीकरण: • अपशिष्ट प्रबंधन: • अपशिष्ट के प्रकार • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन • मलजल (सीवेज) प्रबंध • जैविक उपचार	**192**
4.	**ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन** • ग्रीनहाउस प्रभाव ○ ग्रीन हाउस गैसें • ग्लोबल वार्मिंग ○ ग्लोबल वार्मिंग के कारण ○ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव ○ ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? • समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण: • जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य ○ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) ○ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास ○ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तंत्र	**204**
5.	**जलवायु परिवर्तन शमन तंत्र** • कार्बन क्रेडिट • कार्बन पृथक्करण • कार्बन सिंक • कार्बन ऑफसेटिंग • कार्बन टैक्स	**215**
6.	**ओज़ोन रिक्तीकरण** • ओजोन प्रदूषण ○ ओजोन छिद्र ○ ओजोन क्षरण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ○ किगाली समझौता	**217**

7.	**मरुस्थलीकरण** • कारण • मरुस्थलीकरण के प्रभाव • मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास • मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार के प्रयास	**222**
8.	**वनोन्मूलन** • वनों की कटाई के प्राथमिक कारण • वनों की कटाई के प्रमुख प्रभाव • वनों की कटाई को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास • वनों की कटाई को रोकने के लिए भारत सरकार के प्रयास • वनीकरण	**224**
9.	**जैव विविधता** • जैव विविधता के स्तर ○ आनुवंशिक विविधता ○ प्रजातीय विविधता ○ पारिस्थितिकी तंत्र विविधता • जैव विविधता का महत्व • जैव विविधता हानि	**229**
10.	**जैव विविधता का संरक्षण** • आवश्यकता • यथास्थान/स्थल पर संरक्षण ○ जीवमंडल रिज़र्व ○ राष्ट्रीय उद्यान ○ वन्यजीव अभयारण्य ○ संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक भंडार ○ भारत में पवित्र उपवन ○ समुद्री संरक्षित क्षेत्र ○ होप स्पॉट ○ जैव विविधता हॉटस्पॉट ○ आरक्षित और संरक्षित वन ○ संरक्षण भूखंड ○ बाघ अभयारण्य ○ हाथी गलियारे ○ भारत में शेरों का संरक्षण ○ भारत में गैंडों का संरक्षण: ○ गंगा डॉल्फिन ○ गिद्ध ○ हिम तेंदुआ ○ घड़ियाल ○ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड • एक्स-सीटू/ऑफ-साइट संरक्षण • जैव विविधता संरक्षण पर सरकारी पहलें • प्रमुख अधिनियम	**234**

	• प्रमुख समितियां • प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संगठन और गैर सरकारी संगठन	
11.	**आर्द्रभूमि** • आर्द्रभूमि का महत्व • आर्द्रभूमि के प्रकार • अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयास ○ रामसर कन्वेंशन ○ मॉन्ट्रो रिकॉर्ड • भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रयास ○ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (NPCA) ○ राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 ○ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ○ राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (1985-86) ○ तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियम ○ तटीय विनियमन क्षेत्र पर शैलेश नायक समिति की रिपोर्ट ○ आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017	**265**
12.	**प्रवाल भित्तियाँ** • अनुकूल परिस्थितियां • प्रवाल भित्तियों के प्रकार • प्रवाल विरंजन • प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के वैश्विक प्रयास	**270**
13.	**सदाबहार** • मैंग्रोव का अनुकूलन • मैंग्रोव के फायदे • मैंग्रोव के लिए खतरा • मैंग्रोव संरक्षण के लिए वैश्विक पहल: • भारत में मैंग्रोव का वितरण: • मैंग्रोव संरक्षण के लिए भारत सरकार की पहल:	**275**

प्रिय विद्यार्थी, टॉपर्सनोट्स चुनने के लिए धन्यवाद।

नोट्स में दिए गए QR कोड्स को स्कैन करने लिए टॉपर्स नोट्स ऐप डाउनलोड करे ।

ऐप डाउनलोड करने के लिए दिशा निर्देश देखे :-

ऐप इनस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से या गूगल लेंस से QR स्कैन करें ।

टॉपर्सनोट्स एग्जाम प्रिपरेशन ऐप

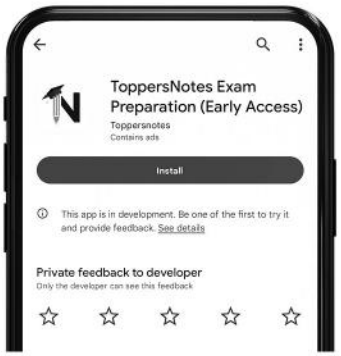

टॉपर्सनोट्स ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से ।

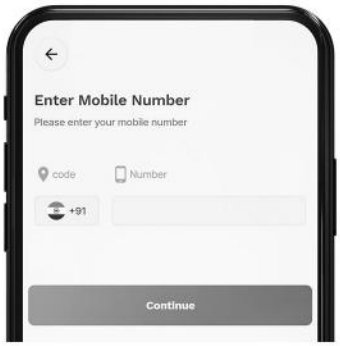

लॉग इन करने के लिए अपना **मोबाइल नंबर** दर्ज करें ।

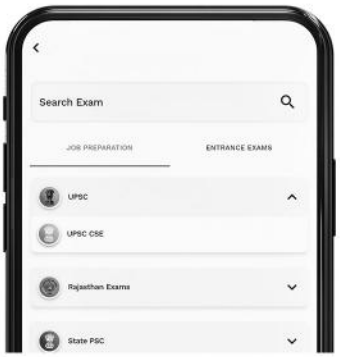

अपनी **परीक्षा श्रेणी** चुनें ।

सर्च बटन पर क्लिक करें ।

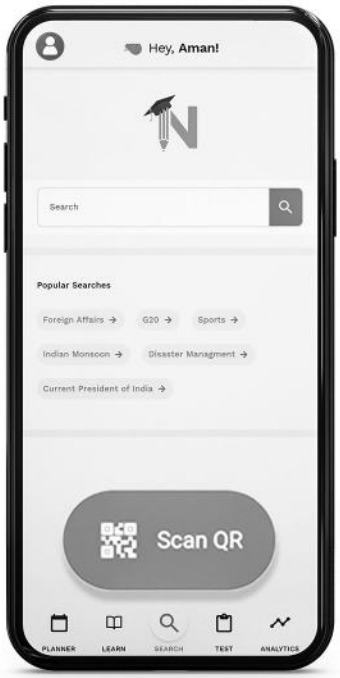

SCAN QR पर क्लिक करें ।

किताब के **QR कोड को स्कैन** करें ।

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए
hello@toppersnotes.com पर मेल करें
या **766 56 41 122** पर whatsapp करें ।

1 CHAPTER विकास

- विकास एक बहुआयामी घटना है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक तत्व होते हैं।
- राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और प्रशासनिक विकास सभी शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है।
- कुछ विद्वान विकास को आधुनिकता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, विशेष रूप से राष्ट्र-निर्माण और सामाजिक-आर्थिक उन्नति के क्षेत्रों में; अन्य इसे परिवर्तन प्लस विकास के रूप में संदर्भित करते हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में संदर्भित करते हैं।
- इसे मानव व्यक्तित्व क्षमता की प्राप्ति के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिसे गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करने के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से पूरा किया जाता है।
    - इस दृष्टिकोण के अनुसार, यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, लेकिन इनमें से एक या अधिक मुख्य चिंताएं अनसुलझी रहती हैं, तो परिणाम को विकास नहीं माना जाता है। विकास की परिभाषा में "आत्मनिर्भरता" और "सांस्कृतिक स्वतंत्रता" शब्द भी शामिल हैं।
- कुछ लोग विकास के तीन मूल मूल्यों के रूप में जीवन निर्वाह, आत्म सम्मान और पसंद की स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं।

मानव विकास के उद्देश्य

- शास्त्रीय विकास अर्थशास्त्र में, विकास को प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया था।
- बाद में, वितरण उद्देश्यों पर केंद्रित विकास की एक व्यापक परिभाषा सौंपी गई।
    - गरीबी और असमानता को कम करने या समाप्त करने के संदर्भ में आर्थिक प्रगति की विशेषता है।
- मानव विकास: विकास के लिए 'जन-केंद्रित' दृष्टिकोण जब विकास को मानव कल्याण के संदर्भ में मापा जाता है, तो व्यक्ति पहले आते हैं।
- 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने इस मुद्दे को हल करने और विकास की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने के लिए मानव विकास सूचकांक (HDI) की धारणा की स्थापना की।
- यह सूचकांक न केवल विकास में, बल्कि नीतिगत वातावरण में भी नाटकीय परिवर्तन लाया, जहाँ सरकार को बाजार की ताकतों की तुलना में अधिक भूमिका दी गई थी।

अमर्त्य सेन के अनुसार: विकास का मूल लक्ष्य "मानव क्षमता का विस्तार करना" है।

- एक व्यक्ति की क्षमता 'कर और प्राणियों' के विभिन्न संयोजनों को दर्शाती है जिसे कोई प्राप्त कर सकता है। यह तब दर्शाता है कि लोग करने या होने में सक्षम हैं।
- नतीजतन, क्षमता एक व्यक्ति की कई जीवन शैली विकल्पों में से चयन करने की क्षमता को संदर्भित करती है।

मानव विकास के लिए दृष्टिकोण

आय दृष्टिकोण	यह मानव विकास के लिए सबसे पुराना दृष्टिकोण है। मानव विकास को आय से जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्तर को दर्शाता है। आय का स्तर जितना ऊँचा होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही ऊँचा होता है।
कल्याण दृष्टिकोण	यह मनुष्य को सभी विकास गतिविधियों के लाभार्थियों या लक्ष्यों के रूप में देखता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक माध्यमिक और सुविधाओं पर उच्च सरकारी व्यय के लिए तर्क देता है। इसके अनुसार लोग विकास में भागीदार नहीं हैं बल्कि केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। सरकार कल्याण पर व्यय को अधिकतम करके मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
बुनियादी जरूरत दृष्टिकोण	प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण। इसके अनुसार छह बुनियादी जरूरतें हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। मानवीय विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की जाती है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रावधान पर बल दिया जाता है।
क्षमता दृष्टिकोण	यह दृष्टिकोण प्रोफेसर अमर्त्य सेन संबंधित है।

	स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण मानव विकास को बढ़ाने की कुंजी है

मानव विकास के घटक

अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास के चार आवश्यक स्तंभ माने हैं।

(i) समानता

- यदि लोगों के मौलिक कौशल में सुधार के संदर्भ में प्रगति पर विचार किया जाता है तो लोगों को अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए।
- इन्हें समानता से संबंधित क्षमताओं के रूप में जाना जाता है।
- समानता से संबंधित क्षमता या अवसरों तक पहुंच प्रदान करने के लिए समाज का संस्थागत ढांचा अधिक लाभप्रद या प्रगतिशील होना चाहिए

(ii) स्थिरता

- मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि इसे 'चलते रहना' और 'लंबे समय तक चलना' चाहिए।
- सतत विकास: जीवमंडल की दीर्घकालिक सुरक्षात्मक क्षमता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
    - इसे विकास के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो भविष्य की पीढ़ियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।
- इसका तात्पर्य यह है कि विकास अनंत काल तक जारी नहीं रह सकता है; बेशक, 'विकास सीमाएँ' हैं।
- सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अंतर-पीढ़ीगत और अंतर-पीढ़ीगत समानता दोनों को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।
- इस प्रकार की असमानता में न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी 'सामाजिक कल्याण' शब्द शामिल है।

(iii)उत्पादकता

- इसे मानव पूंजी निवेश भी कहा जाता है।
- भौतिक पूंजी के अलावा, मानव पूंजी में निवेश से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।
- मानव संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार के साथ वर्तमान संसाधनों की उत्पादकता बढ़ती है।

  थियोडोर डब्ल्यू शुल्त्स के अनुसार- "गरीब लोगों के कल्याण में सुधार के लिए उत्पादन के निर्णायक कारक स्थान, ऊर्जा और फसल भूमि नहीं हैं; निर्णायक कारक जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार है।"

(iv)अधिकारिता

- मानव विकास का एक अन्य पहलू लोगों का सशक्तिकरण है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण।
- शब्द "सशक्तिकरण" अधिकार के विकेंद्रीकरण को संदर्भित करता है ताकि सभी लोगों को सरकार से लाभ हो।
- सशक्तिकरण में राजनीतिक लोकतंत्र का एक रूप शामिल है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के बारे में निर्णय लेते हैं।
- फोकस: जमीनी स्तर पर जुड़ाव पर, जो हाशिए के लोगों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद करता है।

विकास के संकेतक

आर्थिक संकेतक	**राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर** • इस सूचक में वास्तविक आय की गणना स्थिर कीमतों पर की जाती है • यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो यह आर्थिक विकास को इंगित करता है। • जब राष्ट्रीय आय की उच्च दर होती है, तो विकास दर इसके विपरीत अधिक होती है। **प्रति व्यक्ति आय (PCI)** • देश में रहने वाले लोगों की औसत आय प्रति व्यक्ति आय है। • PCI में वृद्धि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है • PCI में वृद्धि देश के आर्थिक कल्याण को इंगित करती है **प्रति व्यक्ति खपत (PCC)** • लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खपत में वृद्धि को PCC में मापा जाता है। • जैसे: वस्त्र, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि • पीसीसी में वृद्धि लोगों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के उच्च आर्थिक विकास को दर्शाती है। **भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक (PQLI) और HDI** • PQLI जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, जीवन स्तर में लोगों का समग्र कल्याण है। • HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है।

	• PQLI और HDI में वृद्धि लोगों के जीवन की गुणवत्ता और इसलिए आर्थिक विकास में सुधार दर्शाती है। **औद्योगिक प्रगति** • यह प्रति व्यक्ति आय और देश के राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है।
सामाजिक संकेतक	• गरीबी दर: यह विकास के लिए पारस्परिक है ○ उदाहरण: यदि PR अधिक है तो विकास धीमा है और इसके विपरीत • स्वास्थ्य कारक: विकास के लिए सीधे आनुपातिक। • यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो विकास भी अच्छा है और इसके विपरीत।

	• महिला सशक्तिकरण: महिलाएं जितनी अधिक सशक्त होंगी, वे विकास में उतना ही अधिक योगदान देंगी, जिससे उनका विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। • देश के विकास में अहम भूमिका निभाएं, उच्च साक्षरता तेजी से विकास में मदद
पर्यावरण संकेतक	• वन क्षेत्र: एक बड़ा वन क्षेत्र बेहतर जीवन स्तर की ओर ले जाएगा। • वन आवरण के नुकसान में योगदान देने वाले कारक जनसंख्या वृद्धि, खाद्य मांग में वृद्धि और कृषि उत्पादकता में गिरावट है। • वायु प्रदूषण: वायु प्रदूषण कम होने से जीने के लिए अधिक व्यवहार्य वातावरण मिलेगा

2 CHAPTER अल्पसंख्यक

- अल्पसंख्यक यह केवल एक सांख्यिकीय माप का उल्लेख नहीं करता है बल्कि इसके बजाय उन व्यक्तियों को संदर्भित कर सकता है जिनका किसी विशेष समाज में बहुत कम या कोई सामाजिक प्रभाव नहीं है।
- अल्पसंख्यक समूह - एक समाजशास्त्रीय श्रेणी जिसे सामाजिक सत्ता के पदों पर बैठे लोगों द्वारा पहचाना जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है और अक्सर उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
- लुई विर्थ के अनुसार अल्पसंख्यक समूह: "लोगों का एक समूह, जो अपनी शारीरिक या सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण, समाज में दूसरों से अलग कर दिया जाता है, जिसमें वे अलग-अलग और असमान व्यवहार के लिए रहते हैं, और इसलिए खुद को सामूहिक वस्तुओं के रूप में मानते हैं भेदभाव। "

अल्पसंख्यक समूह के प्रकार

नस्लीय या जातीय अल्पसंख्यक

- समान विरासत वाले समूह, जैसे कि एक सामान्य भाषा, संस्कृति (कभी-कभी एक धर्म भी शामिल होता है), या दर्शन जो सामान्य वंश या अंतर्विवाह पर जोर देता है।
  लिंग और कामुकता अल्पसंख्यक
- उन्नीसवीं सदी के बाद से, पश्चिमी दुनिया में समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अल्पसंख्यक समूह या समूहों के रूप में मान्यता दी गई है।
- परिवर्णी शब्द "एलजीबीटी" अब अक्सर विभिन्न पहचानों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

धार्मिक अल्पसंख्यक

- धार्मिक अल्पसंख्यकों का एक ऐसा धर्म होता है जो बहुसंख्यक आबादी या सत्तारूढ़ जनसांख्यिकीय समूह से भिन्न होता है।

अक्षमताओं वाले लोग

- विकलांग व्यक्तियों को अब अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों के गठबंधन के रूप में देखा जाता है, जो समाज द्वारा वंचित हैं, न कि वे लोग जो विकलांगता अधिकार आंदोलन के कारण अपनी अक्षमताओं से वंचित हैं।

भारत में अल्पसंख्यक

- भारत का सामाजिक आर्थिक ताना-बाना बेहद जटिल है, क्योंकि यह जाति, धर्म और क्षेत्रीय और भाषाई अंतरों के ढेरों से आकार लेता है।
- साथ ही सदियों से अस्तित्व में रहने वाली भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की एक ऐतिहासिक नींव है।
- इन तत्वों ने भारतीय समाज को एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान किया है। यह परतों और भागों के समूह में विकसित हो गया है जिन्हें अलग और उप-विभाजित किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान

- "अल्पसंख्यक" शब्द को भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, कई समूहों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है।
- अनुच्छेद 29: भारत के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और विकास का अधिकार है।
- अनुच्छेद 30: एक अल्पसंख्यक समूह को धर्म या भाषा की परवाह किए बिना अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान का निर्माण और संचालन करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 51A: जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है
  - धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय मतभेदों के बावजूद सभी भारतीयों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना पैदा करना नागरिकों की जिम्मेदारी है।
  - हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी नागरिकों की है।
- भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के साथ-साथ उनकी जिम्मेदारियों का भी प्रावधान है।

भारत में अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली समस्याएं

- पहचान का संकट
  - सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, इतिहास और विरासत में असमानताओं के कारण अल्पसंख्यक पहचान के प्रश्न से जूझ सकते हैं।
  - परिणामस्वरूप, प्रमुख समुदाय के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती है।

- सुरक्षा का मामला
  - उनके जीवन, संपत्ति और कल्याण के लिए असुरक्षा उनकी विशिष्ट पहचान और समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में कम संख्या के परिणामस्वरूप विकसित होती है।
  - जब किसी समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी के बीच संबंध तनावपूर्ण होते हैं या बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं होते हैं, तो इस भय की भावना को बढ़ाया जा सकता है।
- समानता से संबंधित मुद्दे
  - पूर्वाग्रहों के परिणामस्वरूप, विकास की संभावनाओं से वंचित किया जा सकता है।
  - पहचान में अंतर के परिणामस्वरूप असमानता की भावना विकसित होती है।
- सांप्रदायिक तनाव और दंगे एक समस्या के रूप में
  - सामुदायिक तनाव और दंगों के कारण अल्पसंख्यक हित खतरे में हैं
- राजनीति और लोक सेवा में प्रतिनिधित्व की कमी
  - संविधान के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित सभी लोगों को समानता और समान अवसर की गारंटी दी गई है, लेकिन उनकी संबंधित आबादी कम होने के कारण उनकी प्रस्तुति भी कम है।
- धर्मनिरपेक्षता पर सख्ती से टिके रहने में विफलता
  - हमारे संविधान की आत्मा ही धर्मनिरपेक्ष है, भारत ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया।
  - हालांकि, व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है

अल्पसंख्यकों के प्रति आक्रोश का कारण

- समाज के गरीब तबके का सामाजिक-आर्थिक विकास सामाजिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो कुछ के लिए बहुत विघटनकारी है।
- पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है, जिनके पास पर्याप्त शिक्षा तक पहुंच नहीं है, जो रोजगार या स्कूलों / कॉलेजों में पर्याप्त मात्रा में सीटें लेते हैं, जो सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षित वर्गों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के प्रति अमित्र बनाते हैं।
- आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक/धार्मिक पुनरुत्थानवाद, और महिमामंडन युवाओं के एक बड़े हिस्से के लिए बेहतर काम की संभावनाएं पैदा करने में सरकार की अक्षमता के परिणामस्वरूप हुआ है।

हाल की घटनाएं

- एक उदाहरण था जिसमें एक दलित को मरी हुई गाय की खाल उतारने के लिए पीटा गया था।
- पुणे में मराठों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के पुनर्गठन की मांग की।
- 2015 में दादरी मॉब लिंचिंग मामले में हिंदुओं की भीड़ ने एक मुस्लिम परिवार पर हमला किया था।

अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा और रोजगार

- मुसलमानों की शैक्षिक भागीदारी दर कम है, हालांकि हाल के वर्षों में इसमें सुधार हुआ है।
- घरेलू दान, साथ ही स्थान, शिक्षा में मुस्लिम भागीदारी को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
- अन्य सामाजिक-धार्मिक समूहों की तुलना में मुसलमान ज्यादातर स्वरोजगार करते हैं और नियमित श्रमिकों के रूप में उनकी भागीदारी, विशेष रूप से महानगरीय क्षेत्रों में तृतीयक क्षेत्र में न्यूनतम है।

सरकार की पहल

- प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम
  - अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम/पहल जिसमें कई मंत्रालयों/विभागों की कई योजनाएं/पहल शामिल हैं।
  - अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्य/परिव्यय के 15% को अलग रखना, या यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यकों या महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी वाले स्थानों पर लाभ/धन के प्रवाह की बारीकी से निगरानी की जाती है।
  - अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संभावनाओं को बढ़ाने के लक्ष्य से यह पहल की जा रही है।
  - यह गारंटी देना कि अल्पसंख्यकों के पास आर्थिक गतिविधि और रोजगार में उचित हिस्सा है।
  - अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना।
  - अंतर-सांप्रदायिक असामंजस्य को रोकना और हल करना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM): स्था. 1992 में देश भर में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए।
- कार्यक्रम उस्ताद: इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक पैतृक कला और शिल्प के संरक्षण में कौशल और प्रशिक्षण में सुधार करना है।
- हमारी धरोहर: यह भारतीय संस्कृति के ढांचे में अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन (MAEF): अल्पसंख्यक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की।
- नई मंजिल: शैक्षणिक और कौशल विकास के मामले में दीनी मदरसा स्नातकों को उनके मुख्यधारा के समकक्षों के साथ जोड़ने के लिए एक ब्रिज कोर्स।

आंतरिक सुरक्षा

1 CHAPTER सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक या राजनयिक शक्ति का उपयोग करके सभी प्रकार के राष्ट्रीय संकटों से राज्य और नागरिकों की सुरक्षा।
- **प्रकार**: बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा।
  - **बाह्य सुरक्षा**: विदेशी देशों के हमले के खिलाफ सुरक्षा।
    - **विदेश सुरक्षा प्राधिकरण:** गृह मंत्रालय।
  - **आंतरिक सुरक्षा**: राष्ट्रीय कानून का पालन करना और देश की सीमाओं के भीतर शांति, व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना।
    - **आंतरिक सुरक्षा प्राधिकरण**: रक्षा मंत्रालय।

खतरों के प्रकार

- **आंतरिक खतरे**: देश के भीतर प्रेरित खतरे।
- **बाहरी सहायता प्राप्त आंतरिक खतरे:** देश के भीतर बाहरी सहायता से उत्पन्न खतरे
- **बाहरी खतरे:** देश के बाहर प्रेरित खतरे
- **आंतरिक सहायता प्राप्त बाहरी खतरे:** आंतरिक सहायता से देश के बाहर प्रेरित खतरे।

सुरक्षा के लिए वैश्विक चुनौतियां

परंपरागत	अपरंपरागत
1. पारंपरिक धारणा **सैन्य कारको** और **युद्ध** के **उपयोग**, **शक्ति संतुलन** और **गठबंधन निर्माण** से संबंधित है।	1. यह मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियों को खतरे में डालक**र सेना के उपयोग से परे** है।
2. पारंपरिक धारणा का संबंध **राज्य** और उसकी **शासी संस्थाओं** से है।	2. इसमें **सुरक्षा के व्यापक पहलू** अर्थात भूख, रोग आदि को **शामिल** किया गया।
3. यह केवल **आंतरिक** और **बाहरी खतरों** का राज्य पर प्रभाव तक ही सीमित है।	3. इसमें न केवल **राज्य** बल्कि सभी **व्यक्ति** या **मानव जाति** को भी **शामिल** किया गया है।
4. इसका **मुख्य ध्यान लक्ष्य** हासिल करने के लिए केवल **बल के प्रयोग पर** होता है।	4. इसमें **सहयोग** शामिल है, इसलिए यह मानव या वैश्विक सुरक्षा की रक्षा करता है।

गैर - पारंपरिक सुरक्षा मुद्दे

खाद्य सुरक्षा

- भारत **खाद्य सुरक्षा** के लिए **सुभेद्य** है क्योंकि **जनसंख्या** अभी भी **बढ़** रही है और **2050/2060** तक **स्थिर नहीं** होगी।
- जब **कुपोषण** और **स्टंटिंग** की समस्याओं की बात आती है तो भारत को **सबसे कम विकसित देशों** में **स्थान** दिया जाता है।
- **सुझाव**: लैटिन अमेरिका के **लघु और दीर्घकालिक नीति विकल्पों** को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए **उपभोक्ता, उत्पादक और व्यापार-उन्मुख नीति दृष्टिकोण** के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- राजस्थान के जिला स्तर पर **अति गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबन्धन** (सीएमएएम) **कार्यक्रम** की तर्ज़ पर अन्य कार्यक्रम बनाये जा सकते है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण

- भारत के विकास के साथ **पर्यावरणीय चुनौतियां** भी बढ़ी हैं।
- **उदाहरण**: भारतीय शहरों को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान दिया गया है।
- **सुझाव**: नीदरलैंड और फ्रांस के कदमों को अपनाया जा सकता है, जिन्होंने प्रदूषणकारी गतिविधियों पर कर बढ़ा दिया है, जिसे राजस्व बढ़ाने के बजाय स्थायी ढांचागत विकास में निवेश किया जाता है।
- **ब्राजील के मॉडल** को भारत की **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना** (एनएपीसीसी) में पारदर्शिता की कमी की समस्या से निपटने के लिए अपनाया जा सकता है क्योंकि इसमें **जलवायु परिवर्तन पर अंतर-मंत्रालयी समिति (सीआईएम) समूह** के तहत कई हितधारक शामिल हैं।

पानी की कमी और प्रदूषण

- **भारी आबादी** और **असतत जल संचयन संरचना** के कारण **प्रचुर** मात्रा में **वर्षा** के बावजूद **दुर्लभ जल संसाधनों** पर **दबाव** है
- **सुझाव**: **डेनमार्क मॉडल** अपनाया जा सकता है जो **राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों** के साथ **अनुसंधान संस्थानों** के सहयोग पर केंद्रित है जिसमें सरकार **स्वच्छ जल प्रौद्योगिकियों** पर **अनुवर्ती अनुदान** देती है।
- जल प्रौद्योगिकी में **इजरायल** के **सहयोग से जल संरक्षण** की **नई तकनीकें** खुल सकती हैं।

ऊर्जा सुरक्षा मुद्दे

- **भारत** एक उच्च जीडीपी विकास दर वाला **ऊर्जा खपत करने वाला देश** है।
- **अस्थिर मध्य पूर्व** से **पेट्रोलियम** पर **अत्यधिक निर्भरता** होने से **ऊर्जा संकट** पैदा हो सकता है।
- **सुझाव**: **ट्यूनीशिया** की **"ऊर्जा संरक्षण प्रणाली"** कानून जैसे कानूनों को **पारित** किया जाना चाहिए जो **अक्षय ऊर्जा निवेश** को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र में **कौशल क्षमता बढ़ाने** के लिए **ऊर्जा प्रबंधन** के लिए **राष्ट्रीय कोष** पर निर्भर करता है।
- **चीन** अपने **पड़ोस से परे** देखने और **आर्थिक राजनयिक** साधनों और विभिन्न अन्य **वित्तीय प्रोत्साहनों** के **संयोजन** का **उपयोग** करके **दूर-दूर से ईंधन आयात** करने वाला एक **अच्छा उदाहरण** है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे:

- **संक्रामक रोग, महामारी** आदि
- **खराब स्वास्थ्य अवसंरचना, फुटकर व्यय** (आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च) भारत को इसके लिए सुभेद्य बनाता है।
- **उदाहरण**: गोरखपुर बीआरबी अस्पताल का मामला, जिसके कारण कई बच्चों की मौत हुई।
- **सुझाव**: **स्पष्ट गारंटी और सार्वभौमिक पहुंच कार्यक्रम** पर आधारित **'चिली मॉडल'**, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की **दो स्तरीय प्रणाली** के माध्यम से सभी **नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल** प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, को अपनाया जाना चाहिए।

आपदाएं

- **नियमित बाढ़, सूखा, भूस्खलन** और **चक्रवात** देश की स्थिरता के लिए खतरा बन जाते हैं।
- **उदाहरण**: बिहार, असम बाढ़।
- **सुझाव**: **जापान मॉडल** अपनाया जा सकता है

अवैध प्रवास

- यह **देश की सुरक्षा** के लिए भी **खतरा** है
- **उदाहरण**: बांग्लादेशी अवैध अप्रवासी, रोहिंग्या मुसलमान, आदि।
- **सुझाव**: नागरिकता अधिनियम को फिर से परिभाषित करके कानूनी आप्रवास को प्रोत्साहित करना।
- **अवैध अप्रवासियों** के **दस्तावेज़ीकरण** के लिए **पड़ोसी देशों** के बीच **द्विपक्षीय सहयोग** और एक **बेहतर समाधान** प्राप्त करना।

मानव सुरक्षा के मुद्दे

- **युद्ध, नरसंहार** और **आबादी** के **विस्थापन** से जुड़े खतरों का संयोजन
- **सुझाव**: **असुरक्षा** के प्रभावों को **कम** करने के लिए, **दीर्घकालिक समाधान** के लिए **प्रारंभिक रोकथाम** पर **ध्यान केंद्रित** किया जाना चाहिए।

गरीबी

- **कारण**
  - असतत कृषि।
  - बढ़ती हुई जनसंख्या।
  - अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ता अन्तर
  - भ्रष्टाचार और काला धन।
- **सुझाव**
  - किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा ।
  - परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन।
  - अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करना।
  - भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- **गवर्नेंस बुक में गरीबी के बारे में विस्तार से बताया गया है**

परमाणु सुरक्षा मुद्दे

- **कारण**: रेडियोधर्मी सामग्री हेतु कानूनी संरचना की कमजोरी
- **सार्वभौमिक कवरेज** और **आचार संहिता** के कार्यान्वयन का अभाव।
- **असुरक्षित** और **खुली** सुविधाएं
- **रेडियोधर्मी स्रोतों** को **ट्रैक करना** एक बड़ी **चुनौती** है।
- **उदाहरण**: 1980 के दशक के अंत में ब्राज़ील में हुई गोइआनिया दुर्घटना, जिसने खतरनाक रेडियोलॉजिकल स्रोतों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।
- **सुझाव**
  - **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी** (IAEA) की भूमिका को सुदृढ़ बनाना।
  - **पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण** के भारत के रुख को अपनाना।
  - आचार संहिता के लिए व्यापक **सार्वभौमिक कवरेज।**
  - **स्वैच्छिक** कार्यों में **वृद्धि।**

रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रसार:

- ये **मानवता** के लिए एक **गंभीर खतरा** हैं
- **उदाहरण**: सीरियाई गृहयुद्ध में इन हथियारों का उपयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में एजेंट ऑरेंज का उपयोग
- **सुझाव**: रासायनिक हथियार सम्मेलन (1992) और जैविक हथियार सम्मेलन (1975) को सुदृढ़ बनाना।
- **निर्यात नियंत्रण व्यवस्था** को सुदृढ़ बनाना।

आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे

- **बढ़ते वैश्वीकरण** के साथ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर अधिक से अधिक निर्भर होती जा रही हैं और समग्र रूप से **आर्थिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा** बन गई हैं
- **कारण**:
  - काला धन।
  - उच्च कैश-जीडीपी अनुपात।
  - जाली मुद्रा।
  - व्यापार असंतुलन।
- **सुझाव:**
  - **नागरिक प्रौद्योगिकियों** के तेजी से **परिनियोजन** की सुविधा प्रदान करना।
  - **कर आधार** बढ़ाना।
  - आक्रोश के माध्यम से **आयात** को **कम** करना।

बाहरी राज्य और गैर – राज्य अभिनेताओं की भूमिका

- **बाह्य राज्य अभिकर्ता:** किसी भी इच्छित कार्रवाई के लिए एक संप्रभु राज्य के औपचारिक समर्थन वाली संस्थाएं।
- **गैर-राज्य अभिकर्ता**: अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्ति वाली संस्थाएं लेकिन उनके पास औपचारिक राज्य समर्थन नहीं है।
  - **जैसे**: गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, चरमपंथी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि।

बाहरी राज्यों के अभिनेताओं द्वारा पेश की गयी चुनौतियाँ

- भारत के किसी भी क्षेत्र में **अशांति** (विशेष रूप से **पूर्वोत्तर क्षेत्र** में) का **पड़ोसी देशों** द्वारा **उपयोग** किया जाता है।
  - **उदाहरण**: चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ-साथ भूटान और नेपाल जैसी छोटी शक्तियाँ।
- विभिन्न **विद्रोही**, **नक्सली** और **अलगाववादी संगठनों** को **राजनीतिक-आर्थिक** सहायता, **रसद** सहायता, **सैन्य प्रशिक्षण** और **हथियारों** की **आपूर्ति** प्रदान करना।
- **भारत के खिलाफ** सीमित **युद्ध** छेड़ सकता है
- **साइबर युद्ध** को अंजाम देने के लिए **हैकिंग** और अन्य प्रकार की **जासूसी।**

गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा पेश की गई चुनौतियाँ

- **नशीली दवाओं की तस्करी**: हेरोइन और हशीश के प्रमुख उत्पादकों - **गोल्डन ट्राएंगल** और **गोल्डन क्रिसेंट** (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) से **भारतीय सीमा** की **निकटता** ने इसे **मादक पदार्थों** की **तस्करी** के लिए सुभेद्य बना दिया है।
- **मानव तस्करी**: व्यावसायिक **यौन शोषण** और **जबरन** या **बंधुआ मजदूरी** के लिए भारत के माध्यम से **मनुष्यों** का नियमित रूप से **अवैध व्यापार** किया जाता है।
- **वामपंथी उग्रवाद**: देश के **सबसे कम विकसित क्षेत्रों** में **प्रगति** को **रोकता** है और **प्रचार** के माध्यम से **जनता** को **गुमराह** करता है।
- **पूर्वोत्तर में उग्रवाद**: **अंतर-आदिवासी विवादों**, **बेरोजगारी**, और सीमा पार से **अवैध प्रवासन** ने गैर-राज्य अभिकर्ताओं को इस क्षेत्र में उग्रवाद को एक आकर्षक व्यवसाय में बदलने में मदद की है।
- **आतंकवाद**: **लश्कर-ए-तैयबा**, **जैश-ए-मोहम्मद** आतंकवादी **समूहों** जैसे गैर-राज्य अभिकर्ता देश के लिए एक निरंतर खतरा हैं
- **नागरिक समाज संगठन**: ये संगठन विदेशी सरकारों के लिए **विदेश नीति उपकरण** के रूप में कार्य करते हैं।
  - **सरकारों** और **विदेशी दानदाताओं** से सहायता अनुदान के रूप में **प्राप्त धन** के **दुरुपयोग** और **हेराफेरी** के **गंभीर आरोप** हैं।
- **जाली भारतीय मुद्रा (FICN)**: **अर्थव्यवस्था** को **अस्थिर** करने और **आतंकवाद** के **वित्तपोषण** के लिए पड़ोसी देशों के साथ **खुली सीमाओं** के माध्यम से **भारत** में **तस्करी** की जाती है
- **साइबर हमले:** देश की साइबर अवसंरचना को खराब करने हेतु ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा **क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (सीआईआई)** को **निशाना** बनाया जा रहा है
  - **उदाहरण**: भारत में कोविड -19 वैक्सीन निर्माताओं पर चीनी हैकर समूह **APT 10** (जिसे स्टोन पांडा के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा **कथित तौर पर हमला** किया गया था।

- **हथियारों की तस्करी:** देश में **अस्थिरता** पैदा करने के लिए **पूर्वोत्तर भारत**, **वामपंथी उग्रवाद** प्रभावित **क्षेत्रों** और **जम्मू** और **कश्मीर** में **विद्रोहियों** को गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से तस्करी किए गए **हथियार** और **गोला-बारूद प्रदान** किए जाते हैं।

आंतरिक सुरक्षा

आंतरिक सुरक्षा के पहलू

- प्राधिकरण द्वारा बनाए गए **नियमों और कानूनों को कायम** रखना।
- लोगों की **संप्रभु शक्ति** को **स्वीकार** करना।
- भारत की **राष्ट्रीय संप्रभुता** की **रक्षा** करना।
- भारत की **क्षेत्रीक अखंडता** की **रक्षा** करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय मामलों** में **भारत** को उसके **उचित स्थान** पर उभारना।
- भारत के भीतर **शांतिपूर्ण आंतरिक वातावरण सुनिश्चित** करना।
- हमारे **नागरिकों** के लिए एक ऐसा **वातावरण** तैयार करना जो **न्यायसंगत** हो, **समृद्ध** हो और उन्हें **जीवन** और **आजीविका** के **जोखिमों से बचाता** हो।

आंतरिक खतरों के लिए कारक

स्वतंत्रता के बाद प्रेरित	• अमित्र और शत्रुतापूर्ण पड़ोसी (चीन, पाकिस्तान आदि) • बेरोजगारी और अल्प रोजगार (समावेशी विकास का अभाव)
प्रशासनिक विफलता प्रेरित	• असमान वृद्धि। • संपन्न और असम्पन्न के बीच अंतर बढ़ाना। • शासनीय घाटा। • संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने में विफलता।
दलगत राजनीति से प्रेरित	• साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ाना। • जाति जागरूकता और संघर्ष बढ़ रहे हैं। • साम्प्रदायिकता, जातीयता, भाषाविज्ञान आदि पर आधारित राजनीति। • क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार उन्हें पूरा करने में विफल हो रही है। • उदाहरण: नागालैंड और जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन।
भौगोलिक कारक	• मुख्य भूमि से कटे रहना • सीमाओं के निकट बहुत कठिन उच्चावच।
शासन विफलता	• अक्षम आपराधिक न्याय प्रणाली • बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार • संगठित अपराध में अपराधियों, पुलिस और राजनेताओं के बीच गठजोड़। • विकास का अभाव।

आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां

- **नक्सली खतरे**: वामपंथी उग्रवाद।
- **उत्तर-पूर्व** में **उग्रवाद** और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद।
- **आईटी** उपकरणों का **दुरुपयोग।**
- **पूर्वोत्तर** और अन्य क्षेत्रों में **चीन की दिलचस्पी।**
- **शत्रुतापूर्ण पड़ोस**
- **साम्प्रदायिक हिंसा** और उसका प्रभाव।
- **जातिगत तनाव** और संघर्ष।
- **क्षेत्रीय** और **जातीय** संघर्ष
- **साइबर अपराध** और साइबर सुरक्षा

भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अभिकर्ता

राज्यों की भूमिका

- आंतरिक सुरक्षा **राज्यों के अंतर्गत** आती है।
- **पुलिस बल** राज्य सरकारों के नियंत्रण में होते हैं और किसी भी प्रकार की **आंतरिक अशांति** को सबसे पहले **राज्य बलों द्वारा नियंत्रित** किया जाता है।

केंद्र की भूमिका

- यह आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को संभालने के लिए **सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों** को तैनात करता है
- **नोडल मंत्रालय**: गृह मंत्रालय।
  - सुरक्षा नीति **रक्षा मंत्रालय के दायरे में** आती है, लेकिन इसे **कैबिनेट द्वारा अंतिम रूप** दिया जाता है।

- **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार** की सहायता से सुरक्षा नीति को आकार देने में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।
- **एनएसए**: राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां बनाने में अंतर-मंत्रालयी समन्वय और इनपुट के एकीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB):** दीर्घकालिक विश्लेषण करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- **सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस):** यह समिति भारत की **राष्ट्रीय सुरक्षा** को **बढ़ाने** के लिए समय-समय पर की जाने वाली **विभिन्न पहलों** और भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले **अंतरराष्ट्रीय सौदों से संबंधित मुद्दों** पर चर्चा करती है।

गृह मंत्रालय (एमएचए)

फोकस क्षेत्र	• आंतरिक सुरक्षा। • सीमा नियंत्रण। • केंद्र-राज्य संबंध। • केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। • सीएपीएफ का प्रबंधन। • आपदा प्रबंधन
संवैधानिक जनादेश	• **भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची**: 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' 'राज्य सूची' के अंतर्गत हैं। • **अनुच्छेद 355**: संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।
कार्य	• आंतरिक सुरक्षा स्थिति की **निरंतर निगरानी।** • **उपयुक्त सलाह** जारी करना। • **खुफिया जानकारी** साझा करना और **जनशक्ति** प्रदान करना। • **वित्तीय सहायता।** • राज्यों के **संवैधानिक अधिकारों का सम्मान** करते हुए **सुरक्षा, शांति और सद्भाव** बनाए रखने के लिए **राज्य सरकारों को मार्गदर्शन और विशेषज्ञता।**

इसके दायरे में एजेंसियां	• **सीमा सुरक्षा बल:** सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा करता है।
	• **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस**: नेपाल और भूटान की सीमा।
	• **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (इसमें शामिल हैं)**
	  ○ असम राइफल्स (एआर)
	  ○ सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)
	  ○ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
	  ○ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)
	  ○ भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
	  ○ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी)
	  ○ सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

असम राइफल्स (एआर)

- **स्थापना: 1835** - एकल सैन्यबल के रूप में जिसे '**कछार लेवी**' के रूप में जाना जाता है
- **प्राथमिक लक्ष्य**: ब्रिटिश चाय बागानों और समुदायों को आदिवासी हमलों से बचाना।
- **कार्य**: भारत म्यांमार सीमा की रक्षा के लिए
  - **काउंटर इंसर्जेंसी** से संबंधित कार्यों के लिए
- **मुख्य भूमिका**: इस क्षेत्र को प्रशासन और वाणिज्य के लिए खोलने हेतु, और "**नागरिकों के दाहिने हाथ और सेना के बाएं हाथ**" का **उपनाम** अर्जित किया।
- **स्वतंत्रयोत्तर कर्तव्य:** निम्नलिखित के विकास किया
  - 1962 में **भारत-चीन युद्ध** के दौरान पारंपरिक लड़ाई।

पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता

1 CHAPTER पर्यावरण

- **परिभाषा -** जीवित, निर्जीव घटकों का कुल योग; एक जीव के आसपास के प्रभाव और घटनाएं सम्मिलित होती है।
  - **परिवर्तनशील दोनों जैविक और अजैविक कारक एक प्रवाह में हैं और लगातार बदलते रहते हैं।**
- **पर्यावरण का दायरा**
  - वायुमंडल: गैसों का अदृश्य आवरण
  - जलमंडल: पृथ्वी की सतह पर किसी भी रूप में जल का संचय
  - स्थलमंडल: पृथ्वी का कठोर बाहरी आवरण/पर्पटी
  - जीवमंडल: वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है
- **पर्यावरण के कार्य**
  - **जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक**
    - सौर ऊर्जा, ऑक्सीजन आदि से पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक घटकों से बना होता है।
    - आनुवांशिक और प्रजातियों की विविधता के लिए जिम्मेदार होता है।
  - **गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना**
    - विविध संसाधन और विविधता प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है।
  - **आर्थिक लाभ**
    - मानव जाति के लिए उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है।
    - इन उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करता है।
    - उदाहरण: फर्नीचर, मिट्टी, जमीन आदि के लिए लकड़ी प्रदान करता है।
  - **अपशिष्ट को स्वांगीकरण करता है**
    - वातावरण विभिन्न मानवजनित गतिविधियों से सभी गैसीय कचरे के लिए एक सिंक के रूप में कार्य करता है।
    - जलमंडल सीवेज और अन्य औद्योगिक अपशिष्टों को स्वांगीकरण करता है।
    - स्थलमण्डल उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों के लिए आधार बन गया है।

पर्यावरण क्षरण

- संपत्ति की खपत के माध्यम से पर्यावरण की गिरावट, उदाहरण के लिए, हवा, पानी और मिट्टी और वन्यजीवों का उन्मूलन।
- आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति सामाजिक और पर्यावरणीय गंतव्यों और जरूरतों को पूरा करने के लिए पृथ्वी की सीमा को कम करने के रूप में पर्यावरणीय गिरावट की विशेषता है।
- पर्यावरण क्षरण के विभिन्न रूप:
  - वायु क्षरण (वायु प्रदूषण)
  - जल क्षरण (जल प्रदूषण, सुपोषण आदि)
  - भूमि क्षरण (ठोस अपशिष्ट, ई-कचरा, लैंडफिल, मृदा अपरदन, मृदा निम्नीकरण)
  - वनों की कटाई
  - समुद्र का बढ़ता जल स्तर
  - मरुस्थलीकरण

पर्यावरण कुजनेट वक्र

- आर्थिक विकास शुरू में पर्यावरणीय गिरावट की ओर ले जाता है, लेकिन आर्थिक विकास के एक निश्चित स्तर के बाद, समाज पर्यावरण के साथ अपने संबंधों में सुधार करना शुरू कर देता है और पर्यावरणीय गिरावट का स्तर कम हो जाता है।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ, पर्यावरणीय प्रभाव अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है और उसके बाद कम हो जाता है।
  - प्रारंभिक चरण: अधिक संसाधन → अधिक उत्सर्जन से उत्पन्न अधिक अपशिष्ट।
  - बाद का चरण: आर्थिक विकास → प्रदूषण कम करता है, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी।

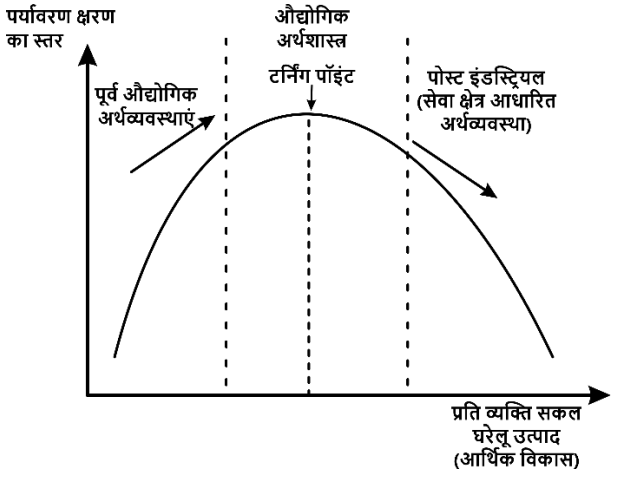

पर्यावरणवाद

- पर्यावरणीय रूप से हानिकारक प्रथाओं को हतोत्साहित करके और एक स्थायी मानव-प्रकृति संबंध स्थापित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संगठनों को बढ़ावा देकर प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और सुरक्षा के लिए राजनीतिक और नैतिक आंदोलन। जिसे हरित आंदोलन या संरक्षण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है।

भारत में प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन

1. विश्नोई आंदोलन

- वर्ष: 17वीं शताब्दी में
- स्थान: खेजड़ली, मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान राज्य।
- नेता: खेजरली और आसपास के गांवों में विश्नोई ग्रामीणों के साथ अमृता देवी।
- उद्देश्य: पवित्र खेजड़ी के पेड़ों को राजा के सैनिकों द्वारा एक नए महल के निर्माण लिए काटे जाने से बचाना।
- आंदोलन के बारे में:
    - गुरु जंभोजी (पेड़ों और जानवरों को नुकसान न करने) की शिक्षाओं से प्रेरित होकर, अमृता देवी ने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर लॉगिंग ऑपरेशन को रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाया और अपने जीवन का बलिदान दिया।
    - इस आंदोलन में 363 विश्नोई ग्रामीण शहीद हुये।
    - जैसे ही राजा को घटना के बारे में पता चला, उन्होंने माफी मांगी और विश्नोई राज्य को संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया, पेड़ों और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

2. चिपको आंदोलन

- वर्ष: 1973
- स्थान: चमोली जिले में और बाद में उत्तराखंड के टिहरी-गढ़वाल जिले में।
- नेता: सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह नेगी, शमशेर सिंह बिष्ट और घनश्याम रतूड़ी।
- उद्देश्य: हिमालय की ढलानों पर वनों की रक्षा करना।
- आंदोलन के बारे में:
    - सुंदरलाल बहुगुणा ने ग्रामीणों को पेड़ों के महत्व के प्रति जागरूक किया।
    - टिहरी-गढ़वाल के आडवाणी गांव की महिलाओं ने पेड़ की टहनियों के चारों ओर पवित्र धागा बांधकर पेड़ों को गले लगाया।
    - वर्ष 1978 में आंदोलन ने गति पकड़ी और तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने इस मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसने अंततः ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया।

3. मौन घाटी बचाओ आंदोलन (Save Silent Valley Movement)

- वर्ष: 1978
- स्थान: साइलेंट वैली, केरल का पलक्कड़ जिला
- नेता: केरल शास्त्र साहित्य परिषद् (केएसएसपी) एक गैर सरकारी संगठन, और कवि-कार्यकर्ता सुघथाकुमारी
- उद्देश्य: पनबिजली परियोजना द्वारा साइलेंट वैली के जंगल को नष्ट होने से बचाना।
- आंदोलन के बारे में:
    - केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने कुंतीपुझा नदी पर एक जलविद्युत बांध का प्रस्ताव रखा जो साइलेंट वैली से होकर गुजरता है।
    - कई गैर सरकारी संगठनों ने इस परियोजना का कड़ा विरोध किया क्योंकि इसमें 8.3 वर्ग किलोमीटर अछूते जंगल के जलमग्न होने का संदेह था।
    - वर्ष 1983 में साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना को बंद कर दिया गया और 1985 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क का उद्घाटन किया गया।

4. जंगल बचाओ आंदोलन

- वर्ष: 1982
- स्थान: बिहार का सिंहभूम जिला
- नेता: सिंहभूम के आदिवासी।
- उद्देश्य: प्राकृतिक साल वन को सागौन से बदलने के सरकार के फैसले को उलट देना।
- आंदोलन के बारे में:
    - बिहार के सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने प्राकृतिक साल के जंगलों को अत्यधिक कीमत वाले सागौन से बदलने के सरकार के फैसले का विरोध किया।
    - यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा में फैल गया था।

5. अप्पिको आंदोलन

- वर्ष: 1983
- स्थान: कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ और शिमोगा जिले में
- नेता: कोई विशिष्ट नेता नहीं, हालांकि पांडुरंग हेगड़े ने सूत्रधार के रूप में कार्य किया।
- उद्देश्य: प्राकृतिक वनों को कटाई और व्यावसायीकरण से बचाना।

- आंदोलन के बारे में
  - चिपको आंदोलन का दक्षिणी संस्करण।
  - स्थानीय रूप से इसे अप्पिको चालुवली कहा जाता है।
  - स्थानीय लोगों ने वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों को गले लगा लिया, जो जागरूकता बढ़ाने के लिए तकनीकों का उपयोग कर रहे थे जैसे कि आंतरिक जंगल में पैदल मार्च, स्लाइड शो, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक आदि।

6. नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA)

- वर्ष: 1985
- स्थान: नर्मदा नदी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है।
- नेता: मेधा पाटकर, बाबा आम्टे, आदिवासी, किसान, पर्यावरणविद् और मानवाधिकार कार्यकर्ता।
- उद्देश्य: नर्मदा नदी पर बन रहे बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ।
- आंदोलन के बारे में
  - सरदार सरोवर बांध के निर्माण से विस्थापित लोगों के लिए उचित पुनर्स्थापन और पुनर्वास सुनिश्चित करने के विरोध के रूप में शुरू किया गया।
  - बाद में पर्यावरण के संरक्षण और घाटी के पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - वर्ष 2000 में, उच्चतम न्यायालय ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण को इस शर्त के साथ मंजूरी दी कि बांध की ऊंचाई 90 मीटर तक बढ़ाई जा सकती है।

7. टिहरी बांध संघर्ष

- वर्ष: 1990 का
- स्थान: उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर।
- नेता: सुंदरलाल बहुगुणा
- उद्देश्य: निवासियों के विस्थापन और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरणीय परिणाम की जांच करना।
- आंदोलन के बारे में:
  - क्षेत्र की उच्च भूकंपीय संवेदनशीलता, टिहरी शहर के साथ वन क्षेत्रों के जलमग्न होने आदि के मुद्दों को उठाया गया।
  - यह आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त लोकप्रिय समर्थन हासिल करने में विफल रहा।

पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

1. मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1972)

- अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून की शुरुआत को चिह्नित किया।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की स्थापना का भी नेतृत्व किया।
- प्रथम सम्मेलन - स्टॉकहोम, स्वीडन वर्ष 1972 में।
- अर्थात् "मानव पर्यावरण पर घोषणा"।
- विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों और पर्यावरण और विकास के बीच संबंधों को संबोधित करने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है।

2. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) (United National Environment Programme)

- गठन: 5 जून 1972,
- मुख्यालय - नैरोबी, केन्या
- संगठन की पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करता है और विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी नीतियों और गतिविधियों को लागू करने में सहायता करता है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनईपी ने वर्ष 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (IPCC) की स्थापना की।
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष के लिए कई कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक और यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य भी है।
- UNEP प्रकाशित करता है
  - वायु गुणवत्ता पर कार्रवाई
  - उत्सर्जन गैप रिपोर्ट
  - वैश्विक पर्यावरण आउटलुक

क्षेत्रीय समुद्री कार्यक्रम (Regional Sea Programme)

- इसकी स्थापना वर्ष 1974 में क्षेत्रीय स्तर पर महासागरों और समुद्रों की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जांच (UN Environment Inquiry)

- वैश्विक वित्तीय प्रणाली के परिवर्तन के माध्यम से एक समावेशी, हरित अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए आवश्यक पूंजी को स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच।
- यह 2014 में लॉन्च किया गया।
- इसकी ऐतिहासिक 2015 रिपोर्ट "द फाइनेंशियल सिस्टम वी नीड" ने पहली बार 'शांत क्रांति' (Quiet Revolution) का खुलासा किया, जो विशेष रूप से कुछ विकासशील देशों के नेतृत्व में हो रही है और सतत विकास के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली के उद्देश्य को नवीनीकृत करने की इसकी क्षमता है।

3. ब्रंटलैंड आयोग

- पहले पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (WCED) के रूप में जाना जाता था।
- सतत विकास की दिशा में काम करने के लिए सभी देशों को एकजुट करने के लिए स्थापित किया गया था।
- आयोग को आधिकारिक तौर पर दिसंबर 1987 में भंग कर दिया गया था, जब उसने "हमारा साझा भविष्य" नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसे अक्टूबर 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है।

- इस रिपोर्ट ने "सतत विकास" शब्द को परिभाषित और लोकप्रिय बनाया।

ब्रंटलैंड रिपोर्ट, 1987
- शीर्षक: हमारा साझा भविष्य: पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट (WCED)
- उद्देश्य: पर्यावरण और विकास को एक इकाई के रूप में चर्चा करना।
- लक्ष्य: आर्थिक और सामाजिक विकास को उन तरीकों से बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ खोजना जो पर्यावरणीय क्षरण, अति-दोहन या प्रदूषण से बचाती है।
- सतत विकास
  - विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।
  - सतत विकास के मूल घटक:
    - पर्यावरण: संसाधन आधार का संरक्षण और वृद्धि करना और धीरे-धीरे प्रौद्योगिकियों और उनके उपयोग को बदलना।
    - सामाजिक समानता: विकासशील देशों को स्थायी जनसंख्या का लक्ष्य बनाकर रोजगार, भोजन, ऊर्जा, पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त करना।
    - आर्थिक विकास: विकसित देशों के रूप में विकासशील देशों के लिए गुणात्मक विकास की समानता सुनिश्चित करके आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना।
  - **सतत विकास के मानदंड**
    - आर्थिक: स्थायी जनसंख्या, सतत् उत्पादकता तथा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की लाभप्रदता।
    - पारिस्थितिक: नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना।
    - तकनीकी: पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियां और उचित अपशिष्ट प्रबंधन।
    - राजनीतिक: जनसंख्या को सशक्त बनाना शांति और व्यवस्था बनाए रखना।
    - सामाजिक-सांस्कृतिक: संसाधन पहुंच और संपत्ति के अधिकार, पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरणीय नैतिकता को शामिल करना।
    - संस्थागत: सतत विकास के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि

4. रियो शिखर सम्मेलन / पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) / रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन / रियो सम्मेलन / पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992)

- जून 1992 में रियो डी जेनेरियो (ब्राजील) में आयोजित किया गया।
- **परिणाम-**
  - **पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणापत्र**
    - भविष्य के सतत विकास में देशों का मार्गदर्शन करने के लिए 27 सिद्धांत दिए।
  - **कार्यसूची 21 (एजेंडा-21)**
    - सतत विकास के लिए एक गैर-बाध्यकारी कार्य योजना।
    - वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन (पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) का परिणाम।
    - संयुक्त राष्ट्र, अन्य बहुपक्षीय संगठनों और दुनिया भर की व्यक्तिगत सरकारों के लिए कार्य एजेंडा जिसे स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर क्रियान्वित किया जा सकता है।
    - एजेंडा 21 में "21" 21वीं सदी को दर्शाता है।
    - उद्देश्य- प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 बनाना चाहिए।
  - **वन सिद्धांत (Forest Principles)**
    - औपचारिक रूप से 'सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहमति के लिए सिद्धांतों के गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी आधिकारिक वक्तव्य' के रूप में जाना जाता है।
    - वानिकी में संरक्षण और सतत विकास के लिए सिफारिशें करता है।
- **इस शिखर सम्मेलन का परिणाम दो कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज थे**-
  - जैविक विविधता पर कन्वेंशन (Convention on Biological Diversity)
  - जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UN Framework Convention on Climate Change)

रियो+5(1997)
- एजेंडा 21 की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष सत्र।
- यूएनजीए ने प्रगति को "असमान" के रूप में मान्यता दी और बढ़ते वैश्वीकरण, आय में बढ़ती असमानताओं और वैश्विक पर्यावरण की निरंतर गिरावट जैसे मुद्दों की पहचान की।
- नया संकल्प - एस-19/2

रियो+10 (2002)
- जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। (जोहान्सबर्ग घोषणा)
- रियो परिणामों का 10 साल का आंकलन करने के लिए
- सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MGD) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की उपलब्धि के साथ, एजेंडा 21 के "पूर्ण कार्यान्वयन" के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

संस्कृति के लिए एजेंडा 21(2002)
- संस्कृति पर पहली विश्व सार्वजनिक बैठक (पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील)।
- स्थानीय सांस्कृतिक नीतियों के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने का विचार आया।

- एजेंडा 21 के विभिन्न उपखंडों में शामिल और G8 देशों से शुरू होने वाले उप-कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से किया जाता है।

सतत विकास पर रियो+20 /संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2012)

- पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के 20 साल बाद और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 के 10-वर्ष बाद आयोजित हुआ।
- अर्थात् रियो 2012 या पृथ्वी सम्मेलन 2012।
- ब्राजील द्वारा 2012 में रियो डी जनेरियो में मेजबानी की गई।
- एजेंडा 21 के प्रति प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की गई।
- सतत विकास पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

सतत विकास शिखर सम्मेलन (2015)

- एजेंडा 2030 / सतत विकास लक्ष्यों पर निर्णय लिया।
- एजेंडा 21 की तर्ज पर 17 लक्ष्य तय किए गए हैं।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility)

- स्थापना: अक्टूबर, 1992
- स्थान - वाशिंगटन, कोलंबिया जिला, संयुक्त राज्य अमेरिका
- वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर स्थापित।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 183 देशों को एकजुट करता है।
- राष्ट्रीय सतत विकास पहल का समर्थन करते हुए वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करता है।
- स्वतंत्र रूप से संचालित वित्तीय संगठन है।
- जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, ओजोन परत, स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी), पारा, स्थायी वन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ शहरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है।
- **निम्नलिखित सम्मेलनों के लिए वित्तीय व्यवस्था के रूप में कार्य करता है**
    - जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
    - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा सम्मेलन (UNFCCC)
    - मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD)
    - स्थायी जैविक प्रदूषकों (पीओपी) पर स्टॉकहोम सम्मेलन
    - (पारा) मिनामाता सम्मेलन
    - संक्रमण वाले देशों में प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का भी समर्थन करता है।

5. अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (International Renowable Energy Agency - IREA)

- **गठन: 26 जनवरी, 2009**
- मुख्यालय: मसदर सिटी, संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- सदस्यता: 160 राज्य और यूरोपीय संघ (EU)
- एक अंतर-सरकारी संगठन, जो सहयोग को सुगम बनाने, ज्ञान को आगे बढ़ाने और अक्षय ऊर्जा को अपनाने और सतत् उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है।
- औद्योगिक और विकासशील दोनों देशों में जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

6. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency - IEA)

- सचिवालय- पेरिस, फ्रांस
- स्थापना - 1974
- 1973 के तेल संकट के मद्देनजर वर्ष 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के ढांचे में स्थापित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन।
- अपने सदस्य राज्यों के लिए नीति सलाहकार के रूप में कार्य करता है, लेकिन गैर-सदस्य देशों, विशेष रूप से चीन, भारत और रूस के साथ भी काम करता है।
- प्रभावी ऊर्जा नीति के "3E" पर ध्यान दें ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security), आर्थिक विकास (Economic Development) और पर्यावरण संरक्षण (Environment Conservation)।
- आईईए सदस्य देश - पिछले साल के शुद्ध आयात के कम से कम 90 दिनों के बराबर कुल तेल स्टॉक स्तर बनाए रखने की आवश्यकता

पर्यावरण के लिए भारतीय प्रयास

1. विज्ञान और पर्यावरण केंद्र

- नई दिल्ली, भारत में स्थित एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान और वकालत संगठन।
- वर्ष 1980 में स्थापित किया गया।
- भारत में पर्यावरण-विकास के मुद्दों पर एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है।
- समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और स्थायी समाधान प्रस्तावित करने के लिए ज्ञान-आधारित सक्रियता का उपयोग करता है।
- वर्ष 2018 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।